प्रथम संस्करण

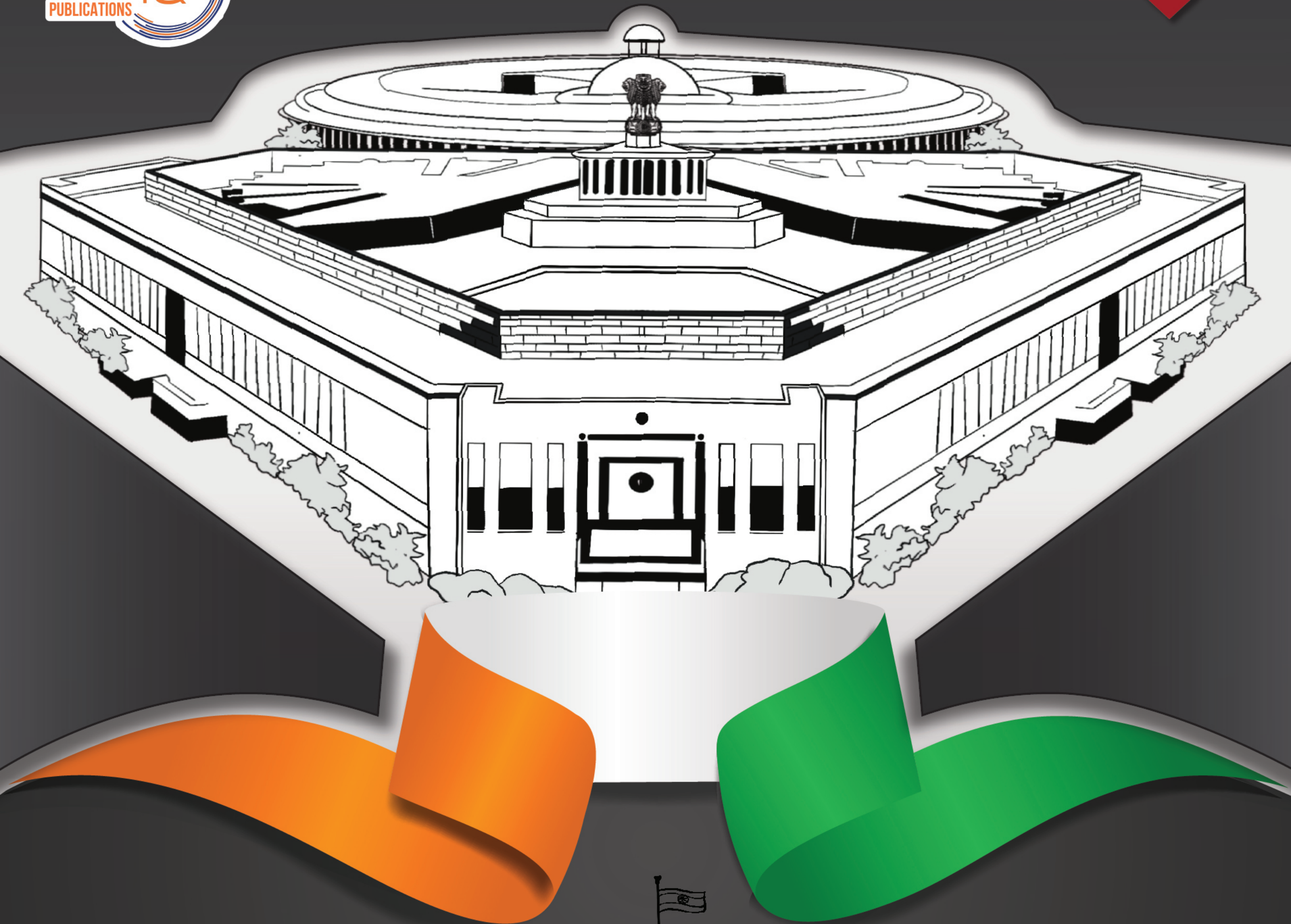

भारत की शासन व्यवस्था

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए उपयोगी

STUDY IQ PUBLICATIONS

संपादक की कलम से

प्रिय साथियों,

हमारी पिछली किताबों (भारत का भूगोल, भूगोल तथ्य एवं सिद्धांत, भारत की राजव्यवस्था तथा आधुनिक भारत का इतिहास) को मिली शानदार प्रतिक्रियाओं के लिए हम आपको विनम्रतापूर्वक धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी किताबें लॉन्च होने के बाद से ही यूपीएससी सेगमेंट में अमेजन और फ्लिपकार्ट के लिए बेस्ट सेलर लिस्ट में हैं।

संघ लोकसेवा आयोग के लिए सर्वोत्कृष्ट, हमारी पूर्व की किताबों को मिली भारी सकारात्मक प्रतिक्रिया से प्रेरणा लेते हुए, हम सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करने के अपने मिशन की दिशा में एक और कदम आगे बढा लगा रहे हैं। स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन आपको हमारी पुस्तक 'भारत की शासन व्यवस्था' का पहला संस्करण प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा है।

यह पुस्तक उन चिंताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिनका सामना छात्रों को सिविल सेवा की तैयारी के दौरान करना पड़ता है। छात्र अक्सर भ्रमित होते हैं कि क्या अध्ययन करना है, कितना अध्ययन करना है, किसी विषय के लिए आवश्यक ज्ञान की गहराई और आयोग द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। इन सबसे ऊपर, समेकित अध्ययन सामग्री की अनुपस्थिति और कई स्रोतों से सूचना हमारे छात्रों की तैयारी में बाधा डालती है।

यह पुस्तक इन समस्याओं से निपटने और छात्रों के ज्ञान के आधार में सुधार करने, उनकी तैयारी के दौरान उनके कीमती समय की बचत करने और उनके सामने आने वाली कई शैक्षणिक गलतफहमियों को दूर करने का एक ईमानदार प्रयास है।

इस पुस्तक की प्रमुख विशेषताएंः

- इस पुस्तक का उद्देश्य यूपीएससी की वर्तमान प्रवृत्तियों और पैटर्न के आधार पर आपकी तैयारी को केंद्रित और प्रासंगिक, पुनरीक्षण-अनुकूल और अप-टू-डेट बनाना है।
- यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की आवश्यकताएं इस पुस्तक का विशेष फोकस हैं।
- हमने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सावधानी बरती है कि सामग्री स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाली हो, ताकि छात्र अपने लाभ के लिए अवधारणाओं को सीख सकें और याद कर सकें।
- जहां भी आवश्यक हो, हमने छात्रों को मुख्य परीक्षा से जुड़ी सभी मौलिक अवधारणाओं को समझने में मदद करने के लिए प्रासंगिक उदाहरण, ऐतिहासिक मामले और तालिकाओं को शामिल किया है।
- पूरी इमानदारी के साथ आपको, आपकी सिविल सेवा परीक्षा की, स्टडी आईक्यू टीम तैयारी में सर्वश्रेष्ठ होने की कामना करती है, और हमें उम्मीद है कि यह पुस्तक आपकी इस अश्वमेध यात्रा में आपकी सहायता अवश्य करेगी।

विषय सूची

1 शासन के विभिन्न दृष्टिकोण 1

1.1 शासन 1
- सरकार की अवधारणा की उत्पत्ति........ 1
- 'शासन' शब्द की उत्पत्ति 2
- शासन का अर्थ 2
- प्रासंगिक अर्थ........ 3

1.2 शासन के पहलू........ 5

1.3 सुशासन........ 6
- सुशासन की विशेषताएँ........ 7
- सुशासन के स्तंभ........ 10

1.4 जवाबदेही........ 10

1.5 तंत्र........ 11
- संस्थागत तंत्र 11
- संस्थागत तंत्र की सीमाएँ........ 18
- गैर-संस्थागत तंत्र 21

1.6 प्रशासनिक जवाबदेही 24

1.7 पारदर्शिता 28
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 .. 28
- आरटीआई अधिनियम की सफलता की कहानियाँ........ 35

1.8 नागरिक घोषणा पत्र 38
- नागरिक घोषणा पत्र के घटक........ 38
- नागरिक घोषणा पत्र के उद्देश्य........ 39
- नागरिक घोषणा पत्र के सिद्धांत........ 39
- नागरिक घोषणा पत्र - भारत का अनुभव 40
- नागरिक घोषणा पत्र को प्रभावी बनाने के लिए दूसरी एआरसी की सिफारिशें........ 42

1.9 शिकायत निवारण तंत्र........ 44
- आम जनता की शिकायतें........ 44

1.10 भारत में शिकायत निवारण तंत्र........ 48
- राष्ट्रीय स्तर पर जीआरएम की संरचना... 48
- राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र...... 50
- वैधानिक और संस्थागत तंत्र........ 50
- शिकायत निवारण तंत्र पर द्वितीय एआरसी 54

1.11 ई-शासन या ई- गवर्नेंस........ 55
- ई-गवर्नेंस की परिभाषाएँ........ 56

1.12 ई-सरकार और ई-शासन 57
- ई-गवर्नेंस के चरण........ 57
- ई-गवर्नेंस के मॉडल........ 58
- ई-गवर्नेंस में अंत:क्रियाओं के प्रकार....... 60
- ई-गवर्नेंस के लाभ........ 63
- ई-गवर्नेंस के अनुप्रयोग........ 67
- सीमाएँ और चुनौतियाँ........ 78
- आगे की राह 80

1.13 शासन में नागरिकों की भागीदारी 83
- शासन में नागरिकों की भागीदारी के रूप 84
- शासन में नागरिकों की भागीदारी के लिए मंच........ 86

2 शासन में विकासात्मक प्रक्रियाएं 89

2.1 विकास प्रक्रिया 89
- विकास की अवधारणा के कुछ प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं 89

2.2 सार्वजनिक नीति........ 91
- अर्थ 91
- सार्वजनिक नीति के उद्देश्य 92

2.3 नीति निर्माण प्रक्रिया 93
- नीति-निर्माण की विशेषताएँ........ 94
- नीतियाँ कैसे बनती हैं? 95
- कार्यसूची की स्थापना........ 95
- समस्याएँ/मुद्दे नीतिगत कार्यसूची तक कैसे पहुँचते हैं? 96

- नीति रूपरेखा निर्माण या नीति निर्माण... 97
- नीति का कार्यान्वयन 99
- भारत में नीति कार्यान्वयन में चुनौतियाँ .99
- नीति निगरानी.. 101
- नीति का मूल्याँकन 102

2.4 भारत में विकास की रणनीतियाँ 104

2.5 नेहरूवादी चरण (1947-1964)........... 104

- नेहरूवादी विकास रणनीति की मुख्य विशेषताएँ थीं.. 104
- औद्योगीकरण 104
- योजना आयोग 105
- भूमि सुधार.. 106
- सीमाएँ.. 107
- शिक्षा और मानव विकास 107

2.6 नेहरु के बाद का चरण (1964-1991) 108

- हरित क्रांति और कृषि विकास............. 108
- गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन........ 109
- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 109

2.7 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 111

- पृष्ठभूमि.. 111
- बैंकों का राष्ट्रीयकरण 111
- राष्ट्रीयकरण का प्रभाव 112
- सीमाएँ.. 112

2.8 आरक्षण की नीति.................................. 113

2.9 उदारीकरण के बाद का चरण (1991-वर्तमान तक)............................ 114

2.10 एलपीजी सुधार...................................... 114

- एलपीजी सुधारों का प्रभाव................... 115
- चुनौतियाँ और आलोचनाएँ................... 116

2.11 मानव विकास... 116

- पृष्ठभूमि.. 117
- भारत में मानव विकास रणनीति........... 117

2.12 सतत विकास.. 120

- भारत में सतत विकास की प्रगति 121
- भारत में सतत विकास की चुनौतियाँ.... 121
- भारत में सतत विकास की भविष्य में संभावनाएँ.. 122
- निष्कर्ष.. 122

2.13 विकास उद्योग 124

2.14 गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)............ 124

- एनजीओ के प्रकार 125
- कानूनी संरचना के आधार पर एनजीओ का वर्गीकरण निम्नलिखित है- 126
- विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका 127
- एनजीओ के समक्ष चुनौतियाँ................ 128
- निष्कर्ष.. 131

2.15 विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत गैर सरकारी संगठन 131

- पर्यावरण.. 131
- शिक्षा... 132
- स्वास्थ्य 133
- महिला सशक्तिकरण 134
- राजनीतिक जागरूकता 134
- मानव अधिकार.................................... 135
- कमजोर वर्ग 136

2.16 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी).......... 137

- भारत में स्वयं सहायता समूहों का विकास 137
- भारत में स्वयं सहायता समूहों की संरचना 137
- एसएचजी का गठन.............................. 138
- एसएचजी के मानदंड............................ 139
- भारत के विकास में एसएचजी के लाभ140
- भारत में स्वयं सहायता समूहों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ...................... 142
- समाधान और आगे की राह.................. 144
- द्वितीय एआरसी की सिफारिशें.............. 146

2.17 एसएचजी और माइक्रोफाइनेंस................147
- सूक्ष्म वित्त की प्रमुख विशेषताएँ हैं 147
- भारत में सूक्ष्म वित्त आंदोलन...............147
- एसएचजी-बैंक सहबद्धता 148
- महिला सशक्तिकरण पर सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के सकारात्मक प्रभावों में शामिल हैं...149
- सीमाएँ...149
- बिहार में जीविका कार्यक्रम और स्वयं सहायता समूह 149
- केरल का कुदुम्बश्री कार्यक्रम 152
- गुजरात में मिशन मंगलम 152

2.18 केस स्टडी 154
- तेलंगाना के राजा एलम्मा की कहानी....154
- कर्नाटक के किसानों की कहानी...........155
- आंध्र प्रदेश से मलैया एसएचजी का पृथक प्रयास..155

2.19 सहकारिता...156
- सहकारिता के सामने चुनौतियाँ............158
- आगे की राह 159

2.20 अनुदानकर्ता संगठन...............................160
- भारत में विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका..161
- भारत में विकास में दाता संगठनों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ...........167

2.21 दान संगठन (Charity Organisations) ----168

3 भारत में नियामक निकाय 173

3.1 परिचय..173
- भारत में नियामक ढाँचे का इतिहास.....173
- भारत में नियामक निकायों की प्रकृति..173
- नियामक निकायों के कार्य...................174
- नियामक निकायों की आवश्यकता........175
- नियामक निकायों के समक्ष चुनौतियाँ...176

3.2 उच्चस्थ नियामक 176
- भारत में उच्चस्थ नियामक की आवश्यकता 177
- उच्चस्थ नियामक को लागू करने में चुनौतियाँ...177
- दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें...178
- नियामक निकायों हेतु आगे की राह 178
- निष्कर्ष..179

3.3 भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)------------------179
- भारतीय रिजर्व बैंक की शक्तियाँ.........181
- चुनौतियाँ...182
- निष्कर्ष..182

3.4 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) 182
- एक नियामक के रूप में सेबी के कार्य 182
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की शक्तियाँ 183
- मुद्दे और चुनौतियाँ...............................185
- आगे की राह 185
- निष्कर्ष..186

3.5 भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)..186
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के उद्देश्य..187
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के कार्य.................................187
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की शक्तियाँ 189
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के समक्ष चुनौतियाँ तथा मुद्दे.....190
- आगे की राह 191
- निष्कर्ष..191

3.6 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)..191
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्य.......192
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की शक्तियाँ.193

- चुनौतियाँ....194
- आगे की राह....194
- निष्कर्ष....195

3.7 अर्ध-न्यायिक निकाय या संस्थाएँ....195
- अर्ध-न्यायिक निकाय क्या हैं?....195
- महत्वपूर्ण अर्ध-न्यायिक निकाय....195
- अर्ध-न्यायिक निकाय के उद्भव का कारण....196
- शासन में अर्ध-न्यायिक निकायों की भूमिका....196
- अर्ध-न्यायिक निकायों के लाभ....197
- अर्द्ध-न्यायिक निकायों के समक्ष चुनौतियाँ....198
- सुधारों की आवश्यकता....199
- निष्कर्ष....200

3.8 भारतीय प्रेस परिषद....200
- भारतीय प्रेस परिषद के बारे में....200
- संघटन....201
- कार्य....201
- भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण के मानदंड....201
- शक्तियाँ....202
- चुनौतियाँ....203
- आगे की राह -....203

4 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 205

4.1 परिचय....205

4.2 उद्देश्य....205

4.3 प्रमुख विशेषताएँ....205
- सीटों का आवंटन....205
- लोकसभा में सीटें भरना....205
- राज्य विधानसभाओं में सीटें भरना....206
- निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन....206
- विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन....206
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी....206
- जिला निर्वाचन अधिकारी....206
- निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी....207
- मतदाता सूची में पंजीकरण....207
- लोकसभा सीटों का आवंटन....209
- राज्यों की विधानसभाओं में सीटों की कुल संख्या....210
- विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में सीटों की कुल संख्या.211
- विधान परिषदों में सीटों का आवंटन ..211

4.4 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951....212
- उद्देश्य....212

4.5 प्रमुख विशेषताएँ....212
- संसद की सदस्यता हेतु अर्हता....212
- राज्य विधायिका की सदस्यता के लिए अर्हता....212
- संसद और राज्य विधानसभाओं की सदस्यता के लिए निरर्हता....213
- आम चुनाव की अधिसूचना....215
- चुनाव के संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र....215
- राजनीतिक दलों का पंजीकरण....216
- चुनाव का संचालन....217
- चुनावों में सामान्य प्रक्रिया....218
- मतदान....219
- मत देने का अधिकार....220
- मतों की गणना....221
- बहुस्थानिक निर्वाचन....221
- परिसंपत्तियों और देनदारियों की घोषणा....221
- निर्वाचन व्यय....222

4.6 चुनाव को लेकर विवाद....222
- उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव याचिकाओं की सुनवाई करना (धारा 80 ए)....222

4.7 भ्रष्ट आचरण..224
4.8 निर्वाचन अपराध....................................225
4.9 चुनाव आयोग की शक्तियाँ 230
- उपचुनाव 230

5 भारत में प्रशासन की संरचना 232
5.1 परिचय 232
5.2 मंत्रिमंडल (मंत्री परिषद) सचिवालय......232
5.3 मंत्रिमंडल सचिव 236
5.4 केंद्रीय सचिवालय...................................238
5.5 मंत्रालय और विभाग 243
5.6 मंत्रालय या विभाग का संगठन...............246
5.7 राजनीतिक प्रमुख....................................246
5.8 सचिवालय संगठन..................................246
5.9 कार्यकारी व्यवस्था..................................250
5.10 सरकार के मौजूदा ढांचे की विशेषताएं और कमियाँ..254
5.11 द्वितीय एआरसी (प्रशासनिक सुधार आयोग) के अनुसार सरकार की संरचना में सुधार के मूल सिद्धांत 256
5.12 राज्य स्तरीय प्रशासन 257
5.13 राज्य सचिवालय की भूमिका..................257
5.14 सचिवालय विभाग और कार्यकारी संगठन/एजेंसी के बीच संबंध 260
5.15 मुख्य सचिव 261
5.16 जिला प्रशासन...262
5.17 सिविल सेवकों को प्रशासनिक सहायता..267

6 लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका 269
6.1 परिचय...269
6.2 क्रमिक विकास...269
6.3 सिविल सेवा का अर्थ 272
6.4 सिविल सेवा और नौकरशाही.................273
- नौकरशाही के प्रकार 274
- नौकरशाही की विशेषताएँ.....................275
- नौकरशाही का महत्व 277
- नौकरशाही के गुण और दोष 279
- भारत में सिविल सेवा की भूमिका और कार्य 281
- सिविल सेवा के समक्ष आने वाले मुद्दे और चुनौतियाँ..284
- सिविल सेवाओं में सुधार के लिए कार्यावली (एजेंडा) 285

6.5 सिविल सेवाओं में अद्यतन सुधार............292
- मिशन कर्मयोगी...................................292
- पार्श्व प्रवेश/ लैटरल एँट्री 294
- सिविल सेवकों के प्रदर्शन का 360 डिग्री मूल्यांकन..297

6.6 सफलता की कहानियाँ 297
- प्रशांत नायर (2007 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी).....................297
- पोमा टुडू (ओडिशा कैडर के 2012 बैच के आईएएस अधिकारी)......................297
- सुरेंद्र कुमार सोलंकी 297
- पी. नरहरि (2001 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी)............298
- सौरभ कुमार (छत्तीसगढ़ कैडर के 2009 बैच के आईएएस अधिकारी)..............298
- डॉ. एमएस लक्ष्मी प्रिया (असम कैडर की 2014 बैच की आईएएस अधिकारी)...298

प्रतिदर्श पेज

अध्याय

2 शासन में विकासात्मक प्रक्रियाएं

विकास प्रक्रिया

- विकास एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जो सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया और वांछित परिणामों की दिशा में प्रगति को संदर्भित करता है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय आयामों सहित मानव कल्याण के विभिन्न पहलुओं में सुधार शामिल है।
- विकास का तात्पर्य देश के नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण में सुधार की प्रक्रिया से है। इसमें बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना, संस्थानों का निर्माण करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना शामिल है।
- विकास का मुख्य उद्देश्य गरीबी, असमानता, बेरोजगारी और पर्यावरणीय गिरावट जैसे मुद्दों को संबोधित करना है।
- प्रभावी शासन एक स्थिर और सहायक नीतिगत वातावरण प्रदान करके, निजी क्षेत्र के निवेश को सुविधाजनक बनाकर, और सार्वजनिक सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करके विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- शासन में विकास का अंतिम लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और एक स्थायी भभिष्य बनाना है।

विकास की अवधारणा के कुछ प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं

आर्थिक विकास

- आर्थिक विकास से तात्पर्य किसी देश, क्षेत्र या समुदाय की आर्थिक भलाई में सुधार की प्रक्रिया से है। इसमें आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, अधिक रोजगार सृजित करने और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रयास और नीतियाँ शामिल हैं।
- आर्थिक विकास कई रूप ले सकता है, जिसमें नए उद्योगों और व्यवसायों का विकास, बुनियादी ढाँचे और परिवहन प्रणालियों में सुधार, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और शिक्षा और मानव पूँजी में वृद्धि शामिल है। आर्थिक विकास का अंतिम लक्ष्य रोजगार सृजित करके, आय बढ़ाकर, गरीबी कम करके और सामाजिक और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देकर व्यक्तियों और समुदायों के जीवन स्तर को बढ़ाना है।
- आर्थिक विकास को अक्सर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), प्रति व्यक्ति आय और रोजगार दर जैसे संकेतकों का उपयोग करके मापा जाता है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आर्थिक विकास का मूल्याँकन अन्य कारकों, जैसे पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक समानता और समग्र मानव विकास के आधार पर भी किया जाना चाहिए। संक्षेप में, आर्थिक विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में सुधार करना है।

© Study IQ Publications

- **सहकारी खेती:** किसानों को अपने संसाधनों को संयोजित करने और सहकारी फार्म बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सहकारी खेती शुरू की गई थी। इन खेतों का स्वामित्व और प्रबंधन संयुक्त रूप से किसानों द्वारा किया जाता था, जो खेती के जोखिमों और लाभों को साझा करते थे। सहकारी खेती का उद्देश्य भूमि जोत के विखंडन को कम करना, आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देना और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना था।
- **भूमि विकास:** कृषि भूमि की उत्पादकता में सुधार करने के लिए सिंचाई, जल निकासी और मिट्टी संरक्षण जैसी बुनियादी सुविधाएँ और सेवाएँ प्रदान करके भूमि विकास की शुरुआत की गई थी। सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में निवेश किया और बीज, उर्वरक और मशीनरी जैसे कृषि खदानों के लिए सब्सिडी प्रदान की।

सीमाएँ

- **राजनीतिक विरोध:** भूमि सुधारों को शक्तिशाली भूस्वामियों के राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा, जिनका यथास्थिति बनाए रखने में निहित स्वार्थ था। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विपक्ष विशेष रूप से मजबूत था, जहाँ जमींदारों के पास महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थी।
- **सीमित कार्यान्वयन:** भूमि सुधारों को लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति के बावजूद उनका कार्यान्वयन सीमित था। जटिल कानूनी प्रणाली और शक्तिशाली भूस्वामियों के प्रतिरोध ने भूमिहीनों को भूमि की पहचान करना और वितरित करना मुश्किल बना दिया। कार्यान्वयन भी राज्यों में असमान था, जिसके कारण भूमि वितरण में क्षेत्रीय असमानताएँ थीं।
- **सहायक सेवाओं का अभाव:** छोटे और सीमाँत किसानों को ऋण, और विपणन सुविधाओं जैसी पर्याप्त सहायक सेवाओं के साथ भूमि सुधार प्रभावी रूप से पूरक नहीं थे। परिणामस्वरूप, कई पुनर्वितरित भूमि अनुत्पादक बनी रही, जिससे कृषि उत्पादकता में गिरावट आई।
- **अपर्याप्त मुआवजा:** अधिग्रहीत भूमि के लिए भूस्वामियों को प्रदान किया जाने वाला मुआवजा प्रायः अपर्याप्त होता है, जिसके कारण भूमि सुधारों के प्रति असंतोष और विरोध होता है।

शिक्षा और मानव विकास

- भारत में नेहरूवादी युग के दौरान शिक्षा को विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता था। नेहरू सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के साधन के रूप में शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, और उन्होंने भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए।
- नेहरू ने माना कि आधुनिक, लोकतांत्रिक और समृद्ध राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि शिक्षा व्यक्तियों को सशक्त कर सकती है, एक कुशल कार्यबल तैयार कर सकती है और सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा दे सकती है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, तत्कालीन सरकार ने शिक्षा तक पहुँच में सुधार और इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई नीतियाँ और कार्यक्रम लागू किए।
- नेहरू की सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की स्थापना थी। UGC विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान आवंटित करने, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और शैक्षणिक मानकों के रख रखाव को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार था। इस पहल ने भारत में उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने में मदद की और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों के विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार की।
- नेहरू सरकार ने स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सहायता और सलाह देने के लिए 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की भी स्थापना की।

© Study IQ Publications

लोकसभा सीटों का आवंटन

क्रम सं.	राज्य का नाम	लोकसभा सीटों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	25
2	अरुणाचल प्रदेश	2
3	असम	14
4	बिहार	40
5	छत्तीसगढ़	11
6	गोवा	2
7	गुजरात	26
8	हरियाणा	10
9	हिमाचल प्रदेश	4
10	झारखंड	14
11	कर्नाटक	28
12	केरल	19
13	मध्य प्रदेश	29
14	महाराष्ट्र	48
15	मणिपुर	2
16	मेघालय	2
17	मिजोरम	1
18	नागालैंड	1
19	ओडिशा	21
20	पंजाब	12
21	राजस्थान	25
22	सिक्किम	1
23	तमिलनाडु	39
24	तेलंगाना	17
25	त्रिपुरा	2
26	उत्तर प्रदेश	80

© Study IQ Publications

- वहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय और विभिन्न प्रशासनिक एजेंसियों और लोक सेवाओं और राजनीतिक व्यवस्था के बीच भी एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।

एक पूर्व मंत्रिमंडल सचिव का मानना है कि मंत्रिमंडल सचिव प्रधानमंत्री की आंखें और कान हैं, जो प्रधानमंत्री (पीएम) को केंद्र सरकार में कामकाज के आधिकारिक संचालन को सक्षम बनाते हैं। लेकिन वह किसी भी मायने में प्रधानमंत्री की ओर से एक प्रहरी या निरीक्षक नहीं है। मंत्रिमंडल सचिव एक कर्मचारी का काम करता है क्योंकि उसका काम मदद करना है न कि निरीक्षण करना।

'सरकार की मशीनरी के पुनर्गठन' (1949) पर गोपालस्वामी आयंगर रिपोर्ट ने मंत्रिमंडल सचिव की स्थिति और भूमिका के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की थी।

- उसे सर्वोच्च रैंक का एक प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए, जिसे उसकी कुशलता, ऊर्जा, पहल और दक्षता के विशेष गुणों के कारण पद हेतु चुना गया हो।
- उन्हें मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रमुख के रूप में समन्वय हासिल करने के साथ-साथ उन मामलों में सरकार के सभी विभागों द्वारा समय पर और प्रभावी कार्रवाई करने का कार्य सौंपा जाना चाहिए जिनमें पूरा मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री इच्छुक हैं।
- उसे वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिए ताकि सभी विभागों के प्रमुखों का विश्वास और सम्मान प्राप्त हो सके।
- उसे प्रशासनिक नियुक्तियों के चयन पर प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों को सलाह देने के लिए गठित सचिवों की समिति का पदेन अध्यक्ष होना चाहिए।
- सेवा में उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, जिससे वह केंद्र सरकार के नियंत्रण के तहत सार्वजनिक सेवाओं के मुख्य सदस्य के रूप में माना जा सके; और जिसके निर्णय और निष्पक्षता पर भरोसा किया जा सके।

स्वतंत्रता के बाद से मंत्रिमंडल सचिवों की सूची

मंत्रिमंडल सचिव	नियुक्ति तिथि	पदानिवृत्ति तिथि
श्री. एन.आर.पिल्लई	06/02/1950	13/05/1953
श्री. वाई.एन.सुक्तंकर	14/05/1953	31/07/1957
श्री. एम.के. वेलोडी	01/08/1957	04/06/1958
श्री. विष्णु सहाय	01/07/1958	10/11/1960
श्री. बी.एन.झा	10/11/1960	08/03/1961
श्री. विष्णु सहाय	09/03/1961	15/04/1962
श्री. एस.एस.खेड़ा	15/04/1962	18/11/1964
श्री. धरम वीर	18/11/1964	27/06/1966
श्री. डीएस जोशी	27/06/1966	31/12/1968
श्री. बी शिवरामन	01/01/1969	30/11/1970
श्री. टी. स्वामीनाथन	01/12/1970	02/11/1972

© Study IQ Publications